

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 14 जनवरी, 2010

विषय:—मॉर्डन इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एवं टेक्नोलॉजी सोसायटी को तहसील रुड़की के ग्राम दहिया की परगना मंगलौर में शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल 0.9952 है भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-395/भूमि व्यवस्था-भूमि कय दिनांक- 30.05.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मॉर्डन इस्टीमेट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी को ग्राम दहिया परगना मंगलौर तहसील रुड़की जनपद हरिद्वार को उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल 0.9952 है भूमि कय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या-472ख के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- कंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- कंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- कंता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी०बी०ए०, डी०सी०ए०, बी०एस०सी०, बी०फार्मा अन्य स्नातक एवं परास्नातक एम०बी०ए०, एम०सी०ए० पाठ्यक्रम तथा बी०एड० कॉलेज की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।



- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हो और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- संस्था द्वारा प्रस्तावित क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन यथा शैक्षणिक संस्थान-बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०एस०सी०, बी०फार्मा अन्य स्नातक एवं परास्नातक (एम०बी०ए०, एम०सी०ए०) पाठ्यक्रम एवं बी०एड० कॉलेज की स्थापना हेतु ही किया जायेगा एवं उक्त बी०एड० कॉलेज का संचालन मार्टन इस्टीमेट मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जायेगा इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित 9852 है० भूमि में से 0.2500 है० भूमि एण्ड सी० टी० ई० के मानकों में परिवर्तन के कारण RIMS विद्यालय के नाम बी० एड० पाठ्यक्रम हेतु क्रय की जा सकेगी, अन्य समस्त भूमि सोसायटी के नाम ही क्रय की जायेगी। RIMS विद्यालय का संचालन इसी सोसायटी द्वारा किया जायेगा।
- 8- उक्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित इकाई द्वारा एन०सी०टी०ई०/उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन आदि के द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेश/निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- उक्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किये जाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में संस्तुति/सहमति/अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।
- 10- किसी दशा में प्रस्तावित कंटाओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 12- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 13- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  
कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

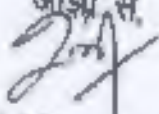
(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव (3)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- कुमारी मनिका शर्मा पुत्री श्री कुबेर दत्त शर्मा, चैयर्समैन मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एवं टेक्नोलॉजी निवासी 101 गोविन्दपुरी कंकरखेड़ा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
- 5- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया सेंटर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(संतोष बड़ोनी)  
अनु सचिव।